उत्तर प्रदेश में पशुपालन का विकास

1355. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत वर्ष उत्तर प्रदेश में पशुपालन विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं चलाई थीं ;

(ख) उक्त योजनायें किन-किन जिलों में चलाई गई ; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा उनमें जिलेवार कितनी प्रगति हुई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सूखे से क्षतिग्रस्त फसल

1356. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष देश में सूखे से कुल कितने मूल्य की फसल क्षतिग्रस्त हुई है तथा उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार ने सूखे की समस्या से निपटने हेतु क्या प्रयास किए हैं ; और

(ग) गत वर्ष सूखे से प्रभावित किसानों को राज्य-वार राहत प्रदान की गई थी ?

कृषि, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान की सरकारों ने 1992 में एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्होंने सूखे की स्थिति में राहत उपायों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मांग है । इन ज्ञापनों के अनुसार 1992 में सूखे की स्थिति के कारण फसलों को निम्नप्रकार क्षति हुई है :–

राज्य	क्षति की सीमा
बिहार	1840.00 करोड़ रुपए फसल हानि का मूल्य)
गुजरात	29.50 लाख मी. टन (उत्पादन में हानि)
कर्नाटक	89.12 लाख हेक्टेयर (प्रभावित फसल क्षेत्र)
केरल	126.42 करोड रुपए (फसल हानि का मूल्य)
मध्य प्रदेश	27.42 लाख हैक्टेयर (प्रभावित फसल क्षेत्र)
महाराष्ट्र	1030.25 करोड रुपए (फसल हानि का मूल्य)
मणिपुर	148.00 करोड रुपए (फसल हानि का मूल्य)
राजस्थान	1154.79 करोड रुपए (फसल हानि का मूल्य)

सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य आरम्भ करने के लिए 1992–93 के दौरान भारत सरकार ने प्रभावित राज्यों को आपदा राहत कोष के केंद्रीय हिस्से के रुप में निम्नलिखित धनराशियां प्रदान की हैं :–

राज्य	करोड़ रुपए
बिहार . .	39.375
गुजरात . .	63.75
कर्नाटक . .	30.375
केरल . .	34.875
मध्य प्रदेश . .	27.75
महाराष्ट्र . .	33.00
मणिपुर . .	0.75
राजस्थान . .	93.00

सूखे की स्थिति में बिहार, गुजरात कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा राजस्थान राज्य की सरकारों द्वारा राहत पुनर्वास हतु निम्नलिखित उपाय किए गए :—

(क) प्रभावित किसानों को कृषि निवेश सहायता प्रदान करना ।

(ख) छोटे और सीमांत किसानों तथा कृषि मजदूरों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करना ।

(ग) प्रभावित पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना ।

(घ) समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल सुनिश्चित करना ।

उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास परियोजना

1357. **श्री राम नरेश यादव:** क्या कृषिमंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास परियोजना को लागू करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को आरंभ करने के लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है या किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश को आंवटित उर्वरक

1358. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1993 के अन्त तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को विभिन्न उर्वरकों को कितनी मात्रा आवंटित की गई थी ;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1993–94 के दौरान इसकी मात्रा में वृद्धि करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) उत्तर प्रदेश को रबी 1992–93 मौसम (अक्तूबर, 1992 से मार्च, 1993 तक) के दौरान उर्वरकों का निम्नप्रकार से आबंटन किया गया :—

उत्पाद	आबंटन ("000टन में)
यूरिया	2194.24
अमोनियम सल्फेट	11.00
अमोनियम क्लोराइड	8.80
सी. ए. एन.	27.50

पोटाश तथा फास्फेट युक्त उर्वरकों पर से अगस्त, 1992 से नियंत्रण हटा लिया गया है।

(ख) और (ग). राज्यों । संघ शासित क्षेत्रों को उर्वरकों का आबंटन संबंधित राज्य संघ की राज्य क्षेत्र की सरकारों तथा उर्वरकों उद्योगों के साथ परामर्श से प्रत्येक फसल-मौसम (खरीफ तथा रबी) के लिये अलग-अलग किया जाता है। उत्तर प्रदेश को 1992–93 के दौरान किये जाने वाले उर्वरकों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले उपभोग रुख तथा विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रमों पर आधारित होगा ।